सुपर बाजार का निजीकरण

2301. **श्री गोपाल सिंह जो. सोलंकी :** क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार ने बगैर कोई निविदा आमंत्रित किए हाल ही में शाखाओं के नवीकरण पर लाखों रुपए खर्च किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले 18 महीनों के दौरान नवीकरण पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि नवीकरण का कार्य सुपर बाजार की प्रबंध समिति की जानकार एक पार्टी को सौंपा गया था ;

(घ) क्या सुपर बाजार ने अपने कुछ विभागों का भी निजीकरण किया है और क्या वर्ष 1994 तक सुपर बाजार के सम्पूर्ण निजीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इस संगठन के स्तर में सुधार किया जा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा विभागों का निजीकरण करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्होंने गत 2 वर्षों में 35 शाखाओं के नवीकरण पर लगभग 13 लाख रुपए की राशि व्यय की है। उन्होंने यह भी कहा है कि सुपर बाजार में एक इंजीनियरी सेल है, जो भंडार के ऐसे सभी कार्य करती है। यह सेल एक इंजीनियर के तहत कार्य को करता है और सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करता है तथा उपयुक्त निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने के बाद भण्डार के पास पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से कार्य प्रतिस्पर्धी दरों पर दिया जाता है। प्राक्कलन, दरों की दिल्ली अनुसूची तथा गैर-अनुसूची वस्तुओं के लिए बाजार औचित्य के आधार पर तैयार किए जाते हैं। बजटीय प्रावधानों को प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कुछ योजनाएं निर्माण कार्य मंत्रालय द्वारा योजना बजट के तहत प्रदत्त वित्तीय सेवाओं से शुरू की जाती हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

SUBSIDIES TO ARTICLES UNDER PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM

2302. **SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :**

SHRIMATI VEENA VERMA :

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether there is a constant pressure from the IMF to cut-down poverty alleviation subsidies in respect of public distribution system ;

(b) if so, whether in view of enhanced support prices of agricultural products like wheat, rice, sugarcane, the subsidies are likely to be increased to maintain the price at the present level ; and

(c) what steps are contemplated to maintain a balance between IMF pressures and internal demands for poverty alleviation programmes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

BASIC OBJECTIVES AND THE ACHIEVEMENTS UNDER REVAMPED PDS

2303. **SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE :** Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) what were the basic objectives of the revamped Public Distribution System ;

(b) details of the targets set under the revamped PDS ;

(c) how far these have been achieved ; and

(d) what steps have been taken by Government to ensure that the benefits of revamped PDS reach the targetted group of Population ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DIS-